



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102020-222710
CG-DL-E-23102020-222710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]
No. 306]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2020/ कार्तिक 1, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2020/ KARTIKA 1, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2020

मामला सं. ए डी (ओआई) 25/2020

विषय : कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातित “लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एलडीपीई)” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 6/30/2020-डीजीटीआर.—कैमिकल्स एंड पैट्रोकेमिकल्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन (जिसे इसके बाद “याचिका” भी कहा गया है) दाखिल किया है, जिसके तहत समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिसे यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित “लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई)”, के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने की मांग की गई है ।

2. आवेदक ने यह दलील दी है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद “लो डेंसिटी पॉलिइथाइलीन (एल डी पी ई)” अथवा “हाई प्रेशर पॉलिइथाइलीन” है जिसमें (क) कंपाउंडेड एल डी पी ई, और (ख) 0.925 जीएम/ क्यूबिक सीएम से अधिक डेंसिटी वाला एल डी पी ई शामिल नहीं हैं (जिसे यहां आगे “विषय वस्तु” या “पीयूसी” भी कहा गया है)। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में कंपाउंडिंग के प्रयोजन के लिए आयात किया गया बेस एल डी पी ई विचाराधीन उत्पाद का दायरे में आता है।
4. पॉलीइथाइलीन एक थर्मोप्लास्टिक है, जो मोनोमर इथाइलीन के पॉलीमराइजेशन से बना है। एलडीपीई पॉलीइथाइलीन का एक प्रकार है, जिसकी डेंसिटी रेंज 0.910 – 0.935 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और इसे प्रायः “ब्रांच” पॉलीइथाइलीन के रूप में उल्लिखित किया जाता है। इसकी मॉलीक्यूलर संरचना कार्बन एटमों की चेन पर कई विषम शाखाओं (कुछ अपेक्षाकृत लम्बी हैं) की मौजूदगी से प्रभावित है।
5. ट्यूबलर या स्टाइर्ड ऑटोक्लेव के माध्यम से हाई प्रेशर वाले रिएक्टरों का उपयोग करके एल पी डी ई का उत्पादन किया जाता है। एक कठिन हाई प्रेशर प्रक्रिया में इथाइलीन फीड को एक प्योरिफाइड रिसाइकल स्टीम के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण में इनीसिएटर और चेन ट्रांसफर एजेंट को शामिल किया जाता है और उसके बाद उसे करीब 300 बार में कंप्रेश किया जाता है। उसके बाद फीड को एक हाइपर कंप्रेशर (2000 से 3000 बार) पॉलिमराइजेशन प्रेशर के साथ कंप्रेश किया जाता है और रिएक्टर सैक्शन में डाला जाता है। आउटलेट पर अक्रिय इथाइलीन को हटा लिया जाता है और उत्पाद को शिपमेंट के लिए पैलेटाइज किया जाता है।
6. इसका उपयोग स्पष्टता, निष्क्रियता, प्रसंस्करण में आसानी, सीलयोग्य, नमी की बाधाओं और अच्छे वैद्युतीय गुणों वाले अनुप्रयोगों में प्रयुक्त किया जाता है। इसका उपयोग ट्रेष बैग, कृषि फिल्मों, ऑटोमेटिक पैकेजिंग फिल्मों और खाने के थैलों और सैनिटरी वस्तुओं, ठंडे खाद्य पैकेजिंग, थ्रिंक और स्ट्रेच हुड फिल्म, सरफेस प्रोटेक्शन फिल्म, लेमिनेशन फिल्म, बबल रैप, अडेसिव टेप बैकिंग फिल्म, मैट्रस निर्माण के लिए फोम इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है।
7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 39 के तहत सीमा शुल्क शीर्ष 3901 के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

समान वस्तु

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अन्तर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे आवश्यक उत्पाद गुणों की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन से आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से कैमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल), जो उत्पाद का एक घरेलू उत्पादक है, ने घरेलू उद्योग के रूप में अपनी सूचना प्रदान की है। आवेदक ने यह दावा किया है कि आरआईएल ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है लेकिन ऐसे आयातों की मात्रा संबद्ध आयातों, भारत में मांग और इसके उत्पादन तथा खपत के संबंध में नगण्य है। इसके अलावा, आर आई एल संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। आरआईएल भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है।

10. उपरोक्त को देखते हुए और विधिवत जांच के बाद प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक उक्त नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन इस नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंड को पूरा करता है।

कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने संबद्ध देशों में कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए आई सी आई एस और प्लेट्स द्वारा प्रकाशित कीमतों पर भरोसा किया है। कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और थाइलैंड में सामान्य मूल्य के प्रयोजन से आवेदक ने इन देशों में आयातों की सी एफ आर कीमत पर भरोसा किया है, जिसमें आयात शुल्क, बीमा, बंदरगाह व्यय, और बंदरगाह से ग्राहक तक और ग्राहक से फैक्ट्री तक स्वदेशी माल भाड़ा व्यय के लिए विधिवत समायोजन किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आवेदक ने प्लेट्स द्वारा यथा सूचित घरेलू रेल कार कीमतों का उल्लेख किया है और उसका स्वदेशी रेल मालभाड़ा लागत के लिए समायोजन किया है ताकि कारखाना बाह्य कीमत निकाली जा सके। आवेदक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य पर वर्तमान जांच शुरुवात के प्रयोजन के लिए उपयुक्त तौर पर विचार किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

12. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तुओं के निर्यात की कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के सौदा वार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और अंतरदेशीय माल भाड़ा व्यय के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

ग. पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना बाह्य स्तर पर तुलना की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत के ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव के परिणामस्वरूप कथित पाटन के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि पाटित आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे उसकी वस्तुसूची में वृद्धि, लाभों, नकदी लाभों और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट हुई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

15. घरेलू उद्योग द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी के निर्धारण, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरुआत करते हैं।

संबद्ध देश

16. इस जांच के लिए संबद्ध देश कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)**17. जांच की अवधि (पीओआई)**

आवेदक ने 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक जांच की अवधि तथा 01 अप्रैल 2016-31 मार्च, 2017, 01 अप्रैल 2017-31 मार्च, 2018, 01 अप्रैल 2018- 31 मार्च, 2019 तक तथा पीओआई तक क्षति की जांच की अवधि के रूप में प्रस्ताव किया है। हालांकि, प्राधिकारी 01 अप्रैल, 2019-30 जून, 2020 (15 महीने) की अवधि जांच की अवधि (पीओआई) तथा 01 अप्रैल, 2016-31 मार्च, 2017, 01 अप्रैल 2017-31 मार्च, 2018, 01 अप्रैल 2018-31 मार्च, 2019 तथा पीओआई को क्षति की जांच की अवधि के रूप में निर्धारित करने के लिए नियम 2(डीए) एवं नियम 22 की व्याख्या के संबंध में इसे उपयुक्त मानते हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि नियम और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के एक पूर्ण लेखांकन वर्ष को शामिल करने पर विचार करते हुए जांच की अवधि उपयुक्त है।

प्रक्रिया

18. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्राचार ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in तथा dd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/ एमएस वर्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
20. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी संबंधित सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उपरोक्त पैरा 19 में उल्लिखित ईमेल पतों पर, नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए नामित प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in/> पर नियमित निगरानी रखें।

समय-सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6 (4) के तहत सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ईमेल पतों अर्थात् adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in तथा dd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि इस नियमावली के स्पष्टीकरण के संदर्भ में सूचना की मांग करने वाले नोटिस और अन्य दस्तावेजों को, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त डिप्लोमेटिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त किया गया माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे डीजीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट पर अर्थात् www.dgtr.gov.in पर इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए नियमित रूप से इसे देख सकते हैं।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (इसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
30. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और /अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
32. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
33. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
34. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

35. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Directorate General of Trade Remedies)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd October, 2020

Case No. AD (OI) 25/2020

Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Low Density Polyethylene (LDPE)” from Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, United Arab Emirates and United States of America.

F. No. 6/30/2020-DGTR.—Chemicals and Petrochemicals Manufacturers Association (hereinafter also referred to as the “Applicant”) has filed an application (also referred to as the “petition”) on behalf of domestic industry, seeking initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Low Density Polyethylene (LDPE)”, originating in or exported from Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, United Arab Emirates and United States of America (also referred to as “subject countries”) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the “Rules”).

2. The Applicant has alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports of LDPE from the subject countries, and has requested for imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods from the subject countries.

Product under Consideration (PUC)

3. The product under consideration is “Low Density Polyethylene (LDPE)” or “high pressure polyethylene”, excluding (a) compounded LDPE, and (b) LDPE having density greater than 0.925 GM/cubic CM (hereinafter also referred to as “subject goods” or “PUC”). It is, however, clarified that base LDPE imported for the purpose of compounding in India is covered within the scope of product under consideration.
4. Polyethylene is a thermoplastic made by polymerisation of monomer ethylene. LDPE is a type of polyethylene, having a density range of 0.910–0.935 grams per cubic centimeter and is often referred to as the “branched” polyethylene. Its molecular structure is characterized by the presence of many asymmetrical branches (some relatively long) on the chain of carbon atoms.
5. LDPE is produced using high-pressure reactors, either through tubular or stirred autoclaves. In a typical high-pressure process, ethylene feed is mixed with a purified recycle stream. Initiator and chain transfer agents are added to the mixture, which is then compressed to approximately 300 bars. The feed is then further compressed to the polymerization pressure in a hyper-compressor (2,000 to 3,000 bars) and fed to the reaction section. At the outlet, unreacted ethylene is removed and recycled. Polyethylene is then fed to an extruder and the product is pelletized for shipment.
6. It is used in applications requiring clarity, inertness, processing ease, sealability, moisture barriers, and good electrical properties. It is also used for producing trash bags, carrier bags, heavy duty bags, agricultural films, automatic packaging films and bags for food and sanitary articles, frozen food packaging, shrink and stretch hood film, surface protection film, lamination film, bubble wrap, adhesive tape backing films, foam for manufacture of mattresses etc.
7. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the custom heading 3901. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

Like Article

8. The Applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and product under consideration imported from the subject countries

are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry and Standing

9. The application has been filed by Chemicals and Petrochemicals Manufacturers Association on behalf of the domestic industry. Reliance Industries Limited (RIL), which is a domestic producer of the product, has provided its information as domestic industry. The Applicant has claimed that RIL has imported the subject goods from the subject countries, but the volume of such imports is negligible in relation to the subject imports, demand in India, and its production and consumption. Further, RIL is not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or importer of the product under consideration in India. RIL is the sole producer of the product under consideration in India.
10. In view of the above, and after due examination, the Authority notes that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2(b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Basis of Alleged Dumping

a. Normal value

11. The Applicant has relied upon the prices published by ICIS and Platts to determine the normal value on the basis of price in the subject countries. For the purpose of normal value in Qatar, Saudi Arabia, UAE, Singapore and Thailand, the Applicant has relied upon the CFR price of imports into these countries as reported by ICIS, duly adjusted for import duty, insurance, port expenses, and inland freight from port to customer and customer to factory. For USA, the Applicant has referred to the delivered domestic railcar prices, reported by Platts, and adjusted the same for inland rail freight cost, to arrive at the ex-factory prices. The evidence provided by the Applicant has been considered appropriate for the purpose of present initiation.

b. Export price

12. The Authority has computed export price for subject goods for the subject countries based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges and inland freight expenses.

c. Dumping margin

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the de-minimis level, and is significant in respect of product under consideration from the subject countries. There is prima facie evidence that the product under consideration is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Evidence of Injury and Causal Link

14. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished information regarding the volume and price effect of the imports, in terms of positive price undercutting and price depression on the domestic industry. The Applicant has claimed that the due to price effect of dumped imports, performance of the domestic industry has been adversely impacted leading to an increase in its inventories, decline in its profitability, and return on capital employed (ROCE). There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from subject countries.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

15. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Countries

16. The subject countries for this investigation are Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, United Arab Emirates and United States of America.

Period of Investigation (POI)

17. The Applicant has proposed period of investigation as 1st April 2019 to 31st March 2020 and injury investigation period as 1st April 2016 – 31st March 2017, 1st April 2017 – 31st March 2018, 1st April 2018 – 31st March 2019, and the POI. The Authority however considers it appropriate, having regard to Rule 2(da), and explanation to rule 22, to fix the period 1st April 2019 – 30th June 2020 (15 months) as the period of investigation (POI), and the period 1st April 2016 – 31st March 2017, 1st April 2017 – 31st March 2018, 1st April 2018 – 31st March 2019, and the POI as the injury investigation period. The Authority considers that the period of investigation is appropriate, considering the rule and inclusion of one full accounting year of the domestic industry in the investigation period.

Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of Information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd14-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF / MS Word format and data files are in MS Excel format.
20. The known exporters, their Governments of the subject countries through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 19 above.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

Time Limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd14-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the

notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
26. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR i.e. www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

Submission of information on confidential basis

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
29. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

35. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

36. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority